(ग) देश में कपड़े की मांग पूरी करने के लिए सरकार मिलों, हथकरघों, विद्युत् चालित करघो और खादी ग्रामोद्योगों को किस प्रकार प्राथमिकता देना चाहती है;

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती आभा मयती): (क) से (ग). यह कहना सच नही है कि सरकार की कोई कपड़ा नीति ही नही है। कपड़ा क्षेत्र के संबंध में जिसके अंतर्गत संगठित और हथकरघा तथा विद्युत् करघा क्षेत्र शामिल है सरकार कुछ निर्देशों का पालन करती रही है। किन्तु प्रत्येक क्षेत्र की सुस्पष्ट सीमा रेखा निर्धारित करने और सूती तथा गैर सूती फाइबर का उपयोग करने संबंधी नीति स्पष्ट करने की आवश्यकता साफ बताई गई है। सभा पटल पर 23 दिसम्बर, 1977 को रखे गये औद्योगिक नीति विवरण मे यह घोषणा करके कि संगठित क्षेत्र की मिलो मे और विद्युत् करघा क्षेत्रो मे बुनाई को विस्तार की अनुमति नही दी जायेगी, तथा लोगो की कपडो की आवश्यकता हथकरघा और खादी क्षेत्रो का प्रगामी विकास करके पूरी की जायेगी इस दिशा मे एक शुरुआत की गई है।

Job Oriented Plan for Backward Areas

8196 SHRI MANORANJAN BHAKTA: Will the Minister of PLANNING be pleased to state:

(a) whether the Planning Commission has worked out a job oriented plan for the backward areas of the country;

(b) if so, the main features of the plan; and

(c) the areas selected for implementing the above plan and whether the Union Territory of Andaman and Nicobar Island has also been included in the plan; if not, the reasons therefor?

THE PRIME MINISTER (SHRI MORARJI DESAI): (a) to (c). In the Five Year Plan 1978—83, which is to be finalised in discussion with the State Governments and Union Territories, the sectoral programmes at the State level will provide for steps to reduce regional disparities. Area planning for full employment, to be achieved over a period of ten years, will be a feature of the development strategy.

The Plan of the Union Territory of Andaman and Nicobar Islands will be plepared with the same objectives.

Expenditure incurred on Filmotsav held in Madras

8197. DR. VASANT KUMAR PANDIT: Will the Minister of INFORMATION AND BROADCASTING be pleased to state:

(a) total expenditure incurred by Government on the Filmotsav held in Madras between 3rd January to 17th January, 1978;

(b) how much of the above has been recovered through screening of foreign films, through advertisements and other sources, and

(c) how much foreign exchange business was negotiated, transacted and actually secured during the Festival?

THE MINISTER OF INFORMATION AND BROADCASTING (SHRI L. K. ADVANI): (a) Government did not directly incur any expenditure as such on Filmotsav' 78. The Festival was jointly organised by the Directorate of Film Festivals and the Film Finance Corporation under an arrangement by which all direct expenditure was met by the latter. This came to Rs. 20.57 lakhs; Government assistance was confined to supervisory role of providing services of key personnel and general administrative assistance.

(b) A total sum of Rs. 25.82 lakhs was recovered by way of sales proceeds through the screening of foreign films (Rs. 24.44 lakhs), through advertisements (Rs. 0.89 lakhs) and sales proceeds from the screening of Indian films (Rs. 0.49 lakhs).

(c) Foreign exchange business of Rs. 71.08 lakhs was negotiated by the Indian Motion Pictures Export Corporation for export of Indian feature films out of which business transacted and actually secured was Rs. 31.22 lakhs. Similarly, business of Rs. 0.50 lakhs was transacted by other organisations on this account.

छठी योजना में हिमाचल प्रदेश के लिए विकास योजनायें

8198. श्री बालक राम: क्या योजना मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार भौगोलिक और जलवायु की दृष्टि से देश के पर्वतीय क्षेत्रों में विकास के लिए, मैदानी इलाकों के लिए बनाई गई योजनाओं से अलग, छटी पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत विकास योजनाये बनाने का है; और

(ख) यदि हा, तो तत्सम्बन्धी मुख्य बातें क्या हैं और इन योजनाओं के परिणामस्वरूप हिमाचल प्रदेश किस प्रकार और कितना लाभान्वित होगा ?

प्रधान मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क) जी, हा।

(ख) राज्य योजनाओं के अंतर्गत देश के पहाड़ी क्षेत्रों के लिए, कृषि-जलवायु की दशाओं, भूभाग, प्राकृतिक संसाधनों और सामाजिक-सांस्कृतिक विशेषताओं के विशिष्ट संदर्भ में उप-योजनाएं तैयार की जायेंगी। हिमाचल प्रदेश के लिए, जो अधिकांश रूप में पहाड़ी क्षेत्र है, राज्य योजना समग्र रूप में उनकी विशेष आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए बनाई जाती है, और उक्त योजना में बहुत उदार रूप में केन्द्रीय सहायता द्वारा सहायता की जाती है।

केन्द्रीय अनुवाद ब्यूरो में कर्मचारियों की संख्या

8199. श्री उग्रसेन :

श्री मही लाल :

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि .

(क) राजभाषा विभाग के केन्द्रीय अनुवाद ब्यूरो मे कुल कितने तकनीकी सहायक, अनुवादक, अनुवाद अधिकारी, सहायक निदेशक और अन्य अधिकारी कार्य कर रहे है;

(ख) उनमें से कितने व्यक्ति, पदवार और वर्गवार अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के हैं और क्या उनके आरक्षित पदों का कोटा भरा गया है;

(ग) यदि नही, तो उसके क्या कारण है,

(घ) क्या अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियो के कुछ अधिकारी जुलाई, 1976 से पदोन्नति के लिए अभ्यावेदन दे रहे है, और

(ङ) यदि हा, तो मंत्रालय के दिनांक 27–11–1972 के कार्यालय ज्ञापन संख्या 27/2/71–एस०सी०टी० और दिनांक 20–7–1974 के कार्यालय ज्ञापन संख्या 10/41/73–एस०सी०टी० के अन्तर्गत इन अभ्यावेदनों पर क्या कार्यवाही की गई है और प्रत्येक वर्ग के आरक्षित कोटे को भरने के लिए सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की जा रही है ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री धनिक लाल मंडल) : (क) से (ग). जानकारी संलग्न है।

(घ) और (ङ). जी हां। अभ्यावेदन